



८५

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 1992/माघ 2, 1913
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 1992/MAGHA 2, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विद्युत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

विदेशी कर प्रभाग

भविष्युतना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1992

प्राधिकार

मानकानि. 60(ग्र).—दोहरे कराधान का अपवर्जन करने के लिए
और आय पर करों को बाबत राजवित्तीय अपवर्जन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रेलिया की सरकार के बीच हमें
उत्तराधिकार, उक्त कराधान के अनुच्छेद 28 के विरो (1) के अनुसार एक
दूसरे को यह अधिष्युक्त करने हुए कि ऐसी बातों में से अंतिम कर दी
गई है जो उत्तराधिकार के भावात में और आस्ट्रेलिया में विधि का बल
देने के लिए अवश्यक है, टिप्पणी के आवान-प्रदान पर 30 दिनों तक,
1991 को प्रवृत्त किया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार प्राधिकार अधिनियम 1961 (1961 का
43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) प्रतिकार अधिनियम, 1964
(1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए।

यह निर्देश देता है कि उक्त कराधान के सभी उपबंधों को भारत संघ में
प्रभावी किया जाएगा।

उपायवन्ध
भारत गणराज्य की सरकार
और
आस्ट्रेलिया सरकार
के बीच
आय पर करों के ममत्वमें
दोहरे कराधान के परिवार
और
राजस्व अपवर्जन को रोकने के
लिए कराधान

भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रेलिया सरकार, आय पर करों
के ममत्वमें दोहरे कराधान द्वारा गम्भीर अपवर्जन को रोकने के लिए
एक कराधान निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार सहमत हैं:

अनुच्छेद-1
वैदिकितक विषय-क्षेत्र

यह कराधान उन अधिकारों पर लागू होगा जो नविराजी राज्यों में
से किसी एक अधिकार दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. विद्यमान कर जिन पर यह करार लागू होगा, इस प्रकार हैं:

(क) आस्ट्रेलिया में:

आस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के संघीय कानून के अंतर्गत लगाया गया आयकर और पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण और उनके उत्पयोग से संबंधित प्राप्तिशील परियोजनाओं के संबंध में संसाधन कियाया कर;

(छ) भारत में:

- आयकर जिसमें उस पर लगाया गया कोई अधिकार; और
- कोपनियों के प्रभार्य लाभों पर लगाया गया अतिकर;

2. यह करार, किन्तु भी समस्य प्रथवा सारत: वैसे ही करों पर लागू होगा जो आस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के संघीय कानून प्रथवा भारत के गणराज्य के कानून के अंतर्गत इस करार पर हस्ताक्षर करने की तरीख के बाब बताना करों के अतिरिक्त प्रथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी प्रयत्नेश्वरों राज्यों के कानूनों में उन करों के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मूलता एक दूसरे को दें जिनके संबंध में यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिवाधाएं

1. इस करार के उद्देश्यों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "आस्ट्रेलिया" शब्द में, जब उसे भौगोलिक प्रयोग में प्रयुक्त किया जाए तिम्नलिखित से विश्व सभी भाषा राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं:

- नोरफोक द्वीप राज्यक्षेत्र;
- किसमस द्वीप राज्यक्षेत्र;
- कोकास (सीलिंग) द्वीप राज्यक्षेत्र;
- आसमोर तथा काटियर द्वीप राज्यक्षेत्र;
- हार्ड द्वीप और मैक डोनाल्ड द्वीप राज्यक्षेत्र; तथा
- कोरल मसुद्र द्वीप राज्यक्षेत्र;

और इसमें आस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय संसाधनों से लगा कोई ऐसा क्षेत्र शामिल है (उसमें उपर्युक्त आपका (i) से (vi) में विविदित राज्यक्षेत्र भी शामिल है) जिनके संबंध में आस्ट्रेलिया का कोई कानून जो फिलहाल प्रवृत्त हो और जो अन्तरास्ट्रीय कानून के समस्य हो और जो महाद्वीपीय शैलक के समूहताल और प्रवर्षमान के प्राकृतिक संसाधनों के किसी उपयोग से संबंधित हो;

(ख) "भारत" शब्द से अधिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का आकाश क्षेत्र और साथ ही अन्य कोई समुद्री क्षेत्र शामिल है जिन पर भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रनुस्ता संबंध प्रथिकार, प्रथम प्रथिकार और शेषाधिकार हैं;

(ग) "संविवाकारी राज्य", "संविवाकारी राज्यों में से कोई एक राज्य" और "दूसरा संविवाकारी राज्य" शब्दों से संदर्भ की प्रयोग के अनुसार आस्ट्रेलिया सरकार प्रथवा भारत सरकार अधिप्रेत हैं जिन्होंने इस करार को निष्पत्र किया है;

(घ) "अधिकार" शब्द में कोई व्यष्टि, कोई कंपनी, अप्लिनियों का कोई अन्य निकाय क्षेत्र कोई अन्य ऐसी सत्ता शामिल है जिसे

कर प्रयोजनों के लिए कर योग्य यूनिट के रूप में माना जाना है;

(इ) "कंपनी" शब्द से ऐसा कोई भी निगमित निकाय प्रथवा ऐसी कोई मता अधिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी प्रथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;

(ज) "संविवाकारी राज्यों में से किसी एक संविवाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविवाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से अधिप्रेत है संदर्भ की प्रयोग के अनुसार आस्ट्रेलिया के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम प्रथवा भारत के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम;

(झ) "कर" शब्द से संदर्भ की अपेक्षानुसार आस्ट्रेलियाई कर प्रथवा भारतीय कर अधिप्रेत है;

- "आस्ट्रेलिया कर" पद से अधिप्रेत है आस्ट्रेलिया द्वारा लगाया गया कर; और
- "भारतीय कर" पद से अधिप्रेत है भारत द्वारा लगाया गया कर,

जो ऐसा कर है जिस पर अनुच्छेद 2 के कारण यह करार लागू होता है लेकिन इस पद में कोई वृद्ध प्रथवा कोई जमिना प्रथवा कोई व्याज शामिल नहीं है जो कर से पंचविंश द्वारा संविवाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत लगाया गया हो;

(झ) "मध्यम प्राधिकारी" शब्द में अधिप्रेत है, आस्ट्रेलिया के मामले में करान्धान आयुक्त प्रथवा आयुक्त का कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि और भारत के मामले में, केवलीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राष्ट्रव्यवस्था विभाग) प्रथवा उनका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि, और

(झ) भारतीय कर से संबंधित "भाय का वर्ष" पद का अधिप्राय है "पूर्ववर्ती वर्ष", जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिवर्तित किया गया है।

2. किसी संविवाकारी राज्य द्वारा इस करारको लागू करने के संबंध में, किसी भी शब्द ज्ञा, जो इस करार में परिवर्तित नहीं है, जब तक संदर्भ में अन्यथा प्रयोग न की गई हो, वही पर्यंत होगा जो उन करों के संबंध में समय-समय पर प्रवृत्त उस राज्य के कानूनों के अधीन होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद-4

नियाम-स्थान

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई अधिक द्वारा संविवाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है तो वह अवित्त उमके कर प्रयोजनों के लिए उम संविवाकारी राज्य का निवासी होगा, लेकिन, यदि कोई अवित्त इस करार के प्रयोजनों के लिए किसी संविवाकारी राज्य का निवासी नहीं है तो उस अवित्त पर कैबिनेट उस राज्य के लोतों से प्राप्त आय के संबंध में ही उस गज्य में कर लगाया जाएगा।

2. जहाँ, पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण, कोई अधिक द्वारा संविवाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उस अवित्त की दैसिक्त निम्नलिखित नियमों के अनुसार नियन्त्रण की जाएगी:

(क) वह अवित्त कैबिनेट उम संविवाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उस अवित्त को कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो;

(ख) यदि उम अवित्त को दोनों संविवाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो प्रथवा उन दोनों में से किसी में भी उपलब्ध नहीं हो तो वह अवित्त कैबिनेट उम संविवाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके माय उम अवित्त के अवित्तन और आर्थिक संबंध घनिष्ठक हिनों का केन्द्र

इस पैराग्राफ़ के प्रयोजनों के लिए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी व्यक्ति की नागरिकता के साथ ही साथ उस व्यक्ति का 'स्थायी' निवास उस संविदाकारी राज्य के साथ उस व्यक्ति के व्यक्तिगत नया आर्थिक संबंधों की गहराई (डिप्री) का निर्धारण करने के कारक होंगे।

3. जहां पैरा (1) के उपबंधों के बारण, किसी व्यक्ति से मिश्र कोई व्यक्ति वोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसे केवल उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके प्रभावी प्रवंध का स्थान स्थित हो।

प्रनुच्छद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस कागर के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारबाहर का यह निश्चित स्थान भवित्वेत है जिसके माध्यम से उद्यम का कारबाहर संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दों के अर्थ-विस्तार के अंतर्गत विशेषता: निम्न-निश्चित प्राप्त हैं:—

- (क) प्रबंध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शास्त्रा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारबाहा;
- (ङ) कोई कर्मशाला;
- (च) आन, तेल अथवा गैस फूप, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निकायण का कोई स्थान;
- (छ) दूसरों के लिए भूमारण सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति का कोई मानवोदाम;
- (ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, आरगाही, अन्तिमित्रा अथवा बागान से संबंधित कार्यकलाप लिए जाते हैं;
- (झ) विक्री स्थान के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले अथवा आदेश प्राप्त करने अथवा मांगे जाने के लिए परिसर;
- (ञ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना अथवा संयंत्र अथवा उपस्करणिका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की ओज अथवा संयंत्रण के लिए किया जाता है;
- (ट) कोई भवन स्थल अथवा निमिण, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा किसी ऐसे स्थल अथवा परियोजना के संबंध में पर्यावरी कार्यकलाप, जहां वह स्थल अथवा परियोजना लक्ष रही है अथवा वे कार्यकलाप (पृथक रूप में अथवा अन्य स्थानों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के साथ) जो महीने से अधिक अवधि के लिए जारी रहते हों।

3. किसी उद्यम का वोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबाहर चलाया जाना माना जाएगा यदि:

- (क) उद्यम द्वारा, उसके लिए अथवा उसकी संविदा के अंतर्गत उस राज्य में महत्वपूर्ण उपस्कर प्रयोग किए जा रहे हों;
- (ख) वह उस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की ओज अथवा निकायण के संबंध में उस राज्य में कार्यकलाप चलाता हो; अथवा
- (ग) वह वोनों संविदाकारी राज्य में से किसी एक संविदाकारी राज्य के शीत कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से सेवाएं, जिनमें प्रबंधकीय सेवाएं और भनुच्छेद 12 के उप-

पैराग्राफ़ (3) (ज) से (ट) तक में उल्लिखित सेवाएं भी शामिल हैं लेकिन प्रदायगिया अथवा शृणुओं के संबंध में वे सेवाएं शामिल नहीं हैं जो भनुच्छेद 12 में यज्ञ-परिमापित रायस्तिया हैं, प्रदान करता हो, लेकिन यदि वे सेवाएं उस राज्य के ही भीतर निम्नानुसार प्रदान की जाती हैं :

- (i) किसी 12 माह की अवधि के भीतर कुल 90 दिनों से प्रधिक की अवधि अथवा प्रवक्ष्यों के लिए अथवा
- (ii) दूसरे उद्यम के लिए यदि वोनों उद्यमों के शीत प्राप्त में भनुच्छेद 9 के उप पैराग्राफ़ (1) (क) और (छ) में वर्णित संबंध हैं।

4. कोई उद्यम केवल निम्ननिश्चित कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा :

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के पूर्णतः भण्डारण अथवा उसके प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टाक रखना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजन के लिए ही उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टाक रखना ;
- (घ) उद्यम के लिए केवल माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदने अथवा खरीदना एकत्र करने के प्रयोजन के लिए कारबाह का निश्चित स्थान रखना ; अथवा
- (इ) उद्यम के लिए केवल विज्ञापन के प्रयोजनार्थ सूचना देने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रथवा इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए जो प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हों, कारबाह का कोई निश्चित स्थान रखना ।

तथापि, इस पैराग्राफ़ के पूर्ववर्ती उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जहां संविदाकारी राज्यों में से किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम इस पैराग्राफ़ में विनिविष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कारबाह का कोई निश्चित स्थान रखता हो ।

5. कोई व्यक्ति, जो स्वतंत्र हैसियत के उस एजेंट से भिन्न हो जिस पर पैराग्राफ़ 6 लागू होता हो, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से किसी एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो, तो उसे प्रथमोऽनुवित राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि :

- (क) उस व्यक्ति को उस उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार है और वह अस्यासतः इसका प्रयोग करता है, जब तक कि उस व्यक्ति के कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं की खरीद तक सीमित नहीं होंगे ;
- (ख) उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, परन्तु वह उस राज्य में अस्यासतः उस उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का भण्डार रखता हो जिसमें से वह व्यक्ति उस उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्य वस्तुओं का परिवान करता है ;
- (ग) वह व्यक्ति उस राज्य के स्वतः उद्यम के लिए अथवा उद्यम के लिए और नियंत्रण करने वाले अन्य उद्यमों अथवा नियंत्रित किए गए अन्य उद्यमों अथवा इसी प्रकार के सामान्य नियंत्रण के मध्यधीन उस उद्यम के लिए पूर्णतः अथवा मुख्यतः प्रार्थना प्राप्त करता है ; अथवा

(ग) इस प्रकार के कार्य करने में, वह व्यक्ति उद्यम से संबंधित माल अथवा पर्याप्त वस्तुओं का उद्यम के लिए उस राज्य में विनियोग करता हो अथवा उनको संसाधित करता हो।

6. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में माल इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कारोबार एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है वह व्यक्ति किसी दलाल अथवा किसी एजेंट के रूप में कारोबार को सामान्य रूप से कर रहा हो। तथापि, जब ऐसे किसी दलाल अथवा एजेंट के कार्यकालाप स्वर्थं उस उद्यम की ओर से अथवा उद्यम की ओर से और नियंत्रण करने वाले और नियंत्रित किए गए उद्यम की ओर से अथवा होने प्रवाह के माध्यम नियंत्रण के प्रधानी उद्यमी उद्यम की ओर से पूर्णतः अथवा मुक्तयतः किए जाते हैं, इस पैराग्राफ के प्रधानी में उस व्यक्ति को कोई दलाल अथवा एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

7. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो दूसरे राज्य में (चाहे स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

8. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताए गए सिद्धान्त इस कारण के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (5) और अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ (5) के प्रयोजनों के लिए यह निर्धारण करने के लिए लागू होते कि क्या दोनों संविदाकारी राज्यों के बाहर कोई स्थायी संस्थापन है और क्या एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के न होने पर कोई उद्यम किसी एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन रखता है।

अनुच्छेद-6

वास्तविक सम्पत्ति (प्रचल सम्पत्ति) से आय

1. वास्तविक सम्पत्ति से आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें वह सम्पत्ति स्थित है।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए “वास्तविक सम्पत्ति” - पर्याप्त है :

(क) आग्रेडिनिया के मामले में, इसका अर्थ यह होगा जो आग्रेडिनियाई कानूनों के अन्तर्गत लगाया जाता हो और जिसमें ये शामिल होते हैं :

- (i) भूमि का कोई पट्टा और भूमि में अथवा उस पर कोई अन्य हित, वह वह विकसित हो अथवा नहीं हो; और
- (ii) संचालन के लिए प्रतिकल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत सुनातान प्राप्त वरने का प्रधिकार या व्यक्ति अथवा अन्य अण्डारों, तेल अथवा गैर कूपों, खदानों अथवा प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण अथवा उपयोग के अन्य स्थानों के संबंध में कार्य करने अथवा खोज करने का प्रधिकार।

(घ) भारत के मामले में, इसका आग्राम ऐसी सम्पत्ति से है जो भारत के कानूनों के अनुसार अचल संपत्ति है और उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) अचल सम्पत्ति के उप-साधन के रूप में संपत्ति;
- (ii) ऐसे प्रधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति के संबंध में सामान्य कानून के अन्तर्गत लागू होते हैं;
- (iii) अचल सम्पत्ति को भागने और संचालन के लिए प्रतिकल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियन्त्रण सुनातान प्राप्त करने के प्रधिकार।

या व्यक्ति अथवा अन्य अण्डारों, तेल अथवा गैर कूपों, खदानों अथवा प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण अथवा उपयोग के अन्य स्थानों के लिए काम करने प्रयत्न उनके संबंध में खोज करने का प्रधिकार।

3. पैराग्राफ (2) के विवेकी यी पैराग्राफ में उल्लिखित भूमि का कोई पट्टा, भूमि में अथवा उपके ऊपर कोई अन्य हित और कोई प्रधिकार अथवा संपत्ति का ऐसे स्थान पर स्थित माना जाएगा जहाँ भूमि, खदान अथवा गैर कूप, खदानों प्राकृतिक संसाधन अथवा संपत्ति, जैसा भी मामला हो, दिक्षा हो अथवा जहाँ अन्वेषण कार्य किया जाता हो।

4. पैराग्राफ (1) के उपर्युक्त वास्तविक संपत्ति के प्रस्तुत उपयोग, जैसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से प्राप्त होने वाली आय पर लागू होंगे।

5. पैराग्राफ (1), (3) और (4) के उपर्युक्त, विवेकी उद्यम की वास्तविक सम्पत्ति में प्रजित आय पर और स्वतंत्र व्यक्तिगत संवादों के नियावान के लिए प्रयुक्त वास्तविक संपत्ति से प्रजित आय पर भी लागू होते हैं।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1. किसी एक संविदाकारी राज्य के लिये उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, किन्तु केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो :

(क) उस स्थायी संस्थापन; अथवा

(ख) उस दूसरे राज्य में उसी साति के प्रयवदः उसी प्रकार के माल अथवा पर्याप्त वस्तुओं का विक्री करता हो अथवा उसी साति के प्रयवदः उसी प्रकार के प्रयवदः अवादायिक कार्यकालाप करता हो जैसे कि उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से लाभ जाते हों।

2. पैराग्राफ (3) के उपर्युक्तों के प्रयवदः रहने हुए, जो एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार करता हो, उस स्थायी संस्थापन को वह लाभ प्राप्त हुए, समस्त जायेग, जिसके प्राप्त होते कि उस स्थिति में अपेक्षा रहने जड़ वह उन्होंने अथवा वैसी ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कानूनों में जगा हुए कोई नियिकन और अन्य उद्यम होना और उद्यम के लाभ जिसका यह स्थायी संस्थापन है अथवा दूसरे उद्यमों के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसके गाय यह कारण है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के नियावान में, उस संविदाकारी राज्य में जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है कर से संबंधित कानून की परिसीमाओं के अनुसार उद्यम के उन लाभों को कटीतियों की स्वीकृति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयवदः के कानूनों के लिए लाभ किए गए आय है (इनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी साथ प्रणालीयिक अवधि भी शामिल है) चाहे इन्हें उस संविदाकारी राज्य में लाभ किया गया हो जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यतः किए गए हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुमा नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पर्याप्त वस्तुएँ आयी गयी हैं।

5. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कारोबार प्राधिकारी किसी स्थायी रसंस्थापन के कारण हुए लाभों की सही रूप का नियावरण करने में असमर्थ

है अथवा उस प्राधिकारी द्वारा उसका पास नगरे में प्रसारण कर्त्तव्याधारी है, तो वहाँ इस अनुच्छेद में वर्णित किसी भी बात का किसी व्यक्ति की करी देनारी का नियोग करने के संबंध में उस राज्य के किसी कानून को लागू करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद के विद्वानों के अनुसार उस सीमा तक कानून को लागू किया जाएगा जहाँ तक उस प्राधिकारी को उपलब्ध सूचना अनुमति प्रदान करती हो।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए स्थायी संस्थापन से कारण हुए सभी जाने वाले लाभों को सब सक वर्षान्वर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया। जाता रहेगा जब तक कि उसके विवरों कोई उचित अथवा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहाँ लाभों में आय की वे मर्दे शामिल हों, जिनका इस कारण के अन्य अनुच्छेदों में व्यवस्था नहीं किया गया हो, तो वहाँ उन अनुच्छेदों के उपर्योगों पर इस अनुच्छेद के उपर्योगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. इस अनुच्छेद में वर्णित किसी भी बात का अनिवार्यता वाला दीमि से प्राप्त किए गए लाभों पर लगाए गए कर के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य के किसी कानून के लागू होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बशर्ते कि यदि इस कारण पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को दोनों संविदाकारी राज्यों में लागू संगत कानून भिन्न हो गया हो (अन्यथा गोण विषय में जिससे कि इसके सामान्य गुणों पर कोई प्रभावों नहीं पड़े), तो संविदाकारी राज्य इस पैराग्राफ के किसी संशोधन के लिए, जो भी उचित हो, सहमत होने की दृष्टि से एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

9. जहाँ:

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी प्रत्यक्षतः अथवा प्रधिक मध्यस्थ न्याय सम्बद्धार्थी के माध्यम से किसी ऐसे न्याय सम्पदा से शामिल, जो उस दूसरे राज्य में किसी कानून के रूप में कर प्रयोजनों के लिए मानी जाती है, किसी न्याय संवदा के न्यासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाए गए किसी उद्यम के व्यापारिक लाभों के किसी हिस्से के लिए लाभ का हकदार है; और

(ख) उस उद्यम के संबंध में, उस स्थानी का, अनुच्छेद 5 के विद्वानों के अनुसार, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन हो;

तो न्यासी द्वारा लगाए गए उद्यम को उस निवासी द्वारा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में नियत किसी न्यासी संस्थापन के माध्यम से लगाया एक अवशाय होना। माना जाएगा और अवशायिक लाभों के उस हिस्से को उस स्थानी संस्थापन के कारण हुआ माना जाएगा।

अनुच्छेद--४

जनशान तथा वायुयान

(1) किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालन में संबंधित नियिकों पर प्राप्त व्याज सहित, जलयान अथवा वायुयान के संचालन से प्राप्त लाभों पर कर के बल उसी राज्य में लगेगा।

(2) पैराग्राफ (1) के उपर्योगों के होने हुए भी, ऐसे लाभों पर कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में लगेगा, जहाँ ऐसे लाभ के बल उस दूसरे राज्य में ल्यप्त स्थानों तक सीमित जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त होते हों।

(3) पैराग्राफ (1) और (2) के उपर्योग किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी पूल सेवा, किसी संपुर्ण परिवहन संचालन संगठन अथवा किसी अन्तरराज्यीय संचालन एजेंसी में भागीदारी के माध्यम से जलयान अथवा वायुयान के संचालन से प्राप्त किए गए लाभों के हिस्से के संबंध में लागू होंगे।

(4) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी एक संविदाकारी राज्य में एक स्थान से उसी राज्य के किसी अन्य स्थान पर जलयान अथवा वायुयान द्वारा यांत्रियों, पशुधन, डाक, माल अथवा पायथ वस्तुओं की दुलाई से प्राप्त होने वाले लाभों को केवल उस राज्य में स्थित स्थानों तक सीमित जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त लाभों के रूप में समाप्त जाएगा :

अनुच्छेद--५

सम्बद्ध उद्यम

(1) जहाँ:

(क) किसी एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम तृप्ते संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहमती होता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति जिसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहमती होते हैं, और दोनों ही मामलों में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिजिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें लागू होती हों जो उन शर्तों से भिन्न हों जो कि एक दूसरे के साथ पूँजी: स्वतंत्र रूप से संबंध रखने वाले स्वतंत्र उद्यमों के बीच में लागू हों। सकती हों, तो ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होते यों वशा में, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परस्तु जो उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तकनीकार कर लगाया जा सकेगा।

(2) इस अनुच्छेद का कोई भी लाभ, किसी व्यक्ति की कर देयता को निर्धारित करने से संबंधित किसी संविदाकारी राज्य के किसी कानून को लागू करने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसमें उन मामलों का नियंत्रण भी शामिल है जहाँ पर किसी उद्यम के कारण होने वाले आय का नियंत्रण करने के लिए उस राज्य के कारबान प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना अपर्याप्त हो, बशर्ते कि इस अनुच्छेद के विद्वानों के अनुसार, जहाँ तक अवश्य हों, कानून लागू किया जाएगा।

(3) वे लाभ जिन पर किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उसी राज्य में कर प्रभारित किया गया हो और जिनको पैराग्राफ

(1) अथवा (2) के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभों में भी शामिल किया गया हो और उन पर उस दूसरे राज्य में कर प्रभारित किया गया हों, और इस प्रकार शामिल किए गए लाभ वे लाभ होते जो दूसरे राज्य के उद्यम को तब प्राप्त हुए होते, यदि उद्यमों के बीच में लागू शर्तें वे होती जो कि एक दूसरे के साथ पूँजी: संबंध रखने वाले स्वतंत्र उद्यमों के बीच में लागू होती हैं, तो उस भवस्था में प्रथमोक्त राज्य, उन लाभों पर प्रभारित राज्य में प्रभारित कर की राशि में उपर्युक्त समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का नियंत्रण करने समय, इस करार के अन्य उपर्योगों पर व्यापक ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्य के सभी प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद--१०

लाभांश

1. किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी द्वारा प्रपने कर के प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्रदा किए गए लाभांश, जिसका कि वह हितभोगी स्वामी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में करारेय होंगे।

2. इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी करारेय होंगे जिसकी लाभांश प्रदा करने वाली कम्पनी प्रपने कर के प्रयोजनों के

लिंग और उम राज्य के कानून के अनुसार वहाँ की निवासी है, परन्तु इस प्रकार से प्रभासित कर की गयी उक्त लाभांशों की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में, “लाभांश” शब्द का अर्थ है शेयरों से आय और अस्य आय जिस पर उसी प्रकार की कागदान अवस्था लागू होती है जो कि उम संविदाकारी राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी कि कर के प्रयोजनों के लिए वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी कम्पनी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगे यदि लाभांशों का हितमोगी अवक्षित किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य के, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उम दूसरे राज्य में स्थित किसी निवित स्थान से स्वतंत्र अवितरण सेवाएं निष्पादित करता हो, और वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निवित स्थान से उपबूत दूप्रामानी की रूप से संबंधित हो। ऐसे किसी मामले में, अनुच्छेद 7 अध्यया अनुच्छेद 14, से जैसा भी मामला हो, के उपबूत लागू होगे।

5. किसी एक संविदाकारी राज्य की किसी निवासी कम्पनी द्वारा किसी ऐसे अवक्षित को अदा किए गए लाभांश जिनका हितमोगी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है, उसे दूसरे राज्य में कर से कूट होती, के सिद्धाय उस सम्पत्ति के, जिसके संबंध में लाभांश दिया गया हो और जो दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निवित स्थान से प्रदाता हप से संबंध हो। वशते कि यह पैराग्राफ किसी ऐसी कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों के माध्यम से लागू नहीं होगा, जो कि आस्ट्रेलियाई करों के प्रयोजन के लिए आस्ट्रेलियाई की निवासी हो और भारतीय कर के प्रयोजनों के लिए भारतीय की निवासी हो।

अनुच्छेद—11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाला व्याज, जिसका कि दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हितमोगी स्वामी है, पर दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है परन्तु इस प्रकार लगाया जाने वाला कर व्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में “व्याज” शब्द में निम्नलिखित शामिल है सरकारी प्रतिशूलियों अथवा वंशपत्रों से प्रदाता इण्डपत्रों से व्याज, जो रेहन के प्राधार पर गारंटीलूदा हों अथवा नहीं और जाहें उन्हें लाभों में भागीदारी का भागीदार, प्राप्त हो अथवा नहीं और किसी अन्य प्रकार की अद्यग्रस्तता से प्राप्त व्याज और साथ ही उस संविदाकारी राज्य, जिसमें आय उद्भूत होती है, के कर से संबंधित कानून द्वारा अद्य देकर प्राप्त आय से एकत्रित अन्य सभी प्रकार की आय, परन्तु इसमें अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित व्याज शामिल नहीं है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितमोगी स्वामी अवक्षित, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज प्रोत्सून हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार लगाता है, अथवा दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी निवित स्थान से स्वतंत्र अवक्षित करता है, और वह अद्यग्रस्तता जिसके

बारे में व्याज अदा किया गया हो, इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निवित स्थान से प्रदाता रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में व्याजिति, अनुच्छेद 7 अध्यया अनुच्छेद 14 के उपबूत लागू होगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में उत्सवत दूप्रामानी माना जाएगा, जब व्याज अदा करने वाला स्थायी वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उपग्रहण, अदा कोई स्वामीय प्राविकरण अथवा कोई अवक्षित जो इसके कर के प्रयोजनों के लिए उम राज्य का निवासी हो। तथापि जहाँ व्याज अदा करने वाला अवक्षित, वहाँ वह अवक्षित किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो, अथवा महीनों, किसी संविदाकारी राज्य में अदा करने वाली संविदाकारी राज्यों के बाहर एक स्थायी संस्थापन अथवा निवित स्थान रखता है जिसके संबंध में वह अद्य निया गया था, जिस पर व्याज की प्रदायनी की जाती है, और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निवित स्थान द्वारा बहन किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज उस राज्य में उपबूत दूप्रामानी माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अदा करने वाले स्थित स्थान स्थित है।

6. जहाँ व्याज अदाकर्ता नया व्याज के हितमोगी स्वामी अवक्षित के बीच अदा उत्सवों और किसी अन्य अवक्षित के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई व्याज की राशि अदा की गई है उस राशि से वह जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और इस प्रकार हकदार अवक्षित के बीच सहमति हुई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित गाँश पर लागू होते हैं। उस मामले में अदा किए गए व्याज की राशि के अविरक्त भाग पर अस्पेक्ट संविदाकारी राज्य के कर से संबंधित कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिसके लिए उपबूतों का पालन किया जाता हो।

अनुच्छेद—12

रायलिट्यों

(1) किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली रायलिट्यों जिनका कि दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हितमोगी स्वामी है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

(2) ऐसी रायलिट्यों पर उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें वे वह होती हैं, और इस राज्य के कानून के अनुसार कर लगेगा परन्तु इस प्रकार कर लगाया गया कर इसमें अधिक नहीं होगा:

(क) निम्नलिखित के मामले में;

(i) उपरोक्त (3) (च) में निर्दिष्ट रायलिट्यों;

(ii) उपरोक्त (3) (ज) से (ठ) के अध्यवौत उपरोक्त (3) (घ) में निर्दिष्ट सेवाओं के लिए अदायनियां अदा के लिए अनुंयाई और सहायक स्वरूप की होती हैं, जिसके लिए उपरोक्त (3) (च) के अधीन अदायनियां अदा के लिए अनुंयाई होती हैं, अथवा

(iii) उपरोक्त (3) (च) में निर्दिष्ट रायलिट्यों जो कि उपरोक्त (3) (च) में उल्लिखित उपस्कर से संबंधित हैं:

रायलिट्यों की सकल राशि का 10 प्रतिशत; और

(क) और अन्य रायलिट्यों के मामले में:

(i) प्रथम 5 वर्षों के दौरान की वह आय जिसके संबंध में यह करार किया गया है।

(क) जहाँ पर सरकार अथवा उम राज्य का कोई राजनीतिक उपग्रहण, अदा कोई सार्वजनिक धेत्र की क्षमता अदाकर्ता हो; रायलिट्यों की सकल राशि का 15 प्रतिशत; और

(अ) प्रथम सभी मामलों में: रायलिंटों की सबसे राशि का 20 प्रतिशत; और

(इ) आय के सभी अनुबंधी वर्षों के बीच: रायलिंटों की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

(३) इन अनुच्छेद में रायलिंटों ग्रन्थ का प्रधर्ष है—अवायवियों अथवा क्रेडिट, जहाँ आवधिक हों अथवा नहीं, और जो उस सीमा तक विनियोगित हों जहाँ तक वे अवायवियों निम्नलिखित के लिए प्रतिक्रिया के रूप में की जानी हैं :

(क) किसी कापीराइट, ऐटेन्ट, डिजाइन अथवा नपूते, ल्यान, गुप्त कार्यालय अथवा प्रक्रिया, ट्रेडमार्क अथवा अन्य जैसे सम्पन्न अथवा अधिकार के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार;

(ख) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकर के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार;

(ग) वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक ज्ञानकारी अथवा सूचना की आपूर्ति;

(घ) तकनीकी अथवा पर्यामरणाली सेवाएं (तकनीकी अथवा अन्य कार्मिक सेवाओं सहित) प्रदान करना जो कि किसी सम्पन्न अथवा अधिकार के उपयोग अथवा इस्तेमाल के लिए अनुबंधी और सहायक हैं; जैसा कि उप-पैराग्राफ (क) में उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई उपकर जैसा कि उप-पैराग्राफ (घ) में उल्लेख किया गया है अथवा ऐसी कोई ज्ञानकारी अथवा सूचना जैसा कि उप-पैराग्राफ (ग) में उल्लिखित है;

(ङ.) निम्नलिखित को प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार :

- स्लिपिंग फिल्में;
- क्रूरदर्जन के उपयोग के लिए किलों और बीड़ियों द्वारा अथवा
- नेहियों प्रसारण के संबंध में उपयोग के लिए द्वारा

(घ) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) में उल्लिखित किसी सम्पन्न अथवा अधिकार के उपयोग अथवा आपूर्ति के संबंध में ५०% अथवा अधिक परिवर्तन; अथवा

(छ) ऐसी सेवाएं (तकनीकी अथवा अन्य कार्मिक सेवाओं सहित) प्रदान करना जो तकनीकी ज्ञानकारी, अनुभव, कौशल, विज्ञान प्रक्रिया तात्पुरता करनी हों अथवा जिसमें किसी तकनीकी लालां अथवा डिजाइन का विकास नथा अन्तरण आमिल हों;

किन्तु उक्त पद में उप-पैराग्राफ (घ) और (छ) में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित अदायगियों अथवा क्रेडिट मामिल नहीं हैं जो कि निम्नलिखित के संबंध में दिये जाते हैं;

(अ) वे सेवाएं जो अनुबंधी और सहायक स्वरूप की हों, और अन्तर्नीय रूप से और अनिवार्य रूप से सम्पन्न को विक्री में सम्बद्ध हों;

(इ) वे सेवाएं जो अनुबंधी अथवा सहायक वाले वाले जनयाती, वायानी, कन्टेनरी अथवा ग्राम्य उपकरणों को किराये पर उपलब्ध के लिए अनुबंधी और सहायक स्वरूप की हों;

(अ) किसी शैक्षिक संस्थान में अध्यापन अथवा शिक्षण के लिए;

(ट) अवायवियों अथवा क्रेडिट देने वाले व्यापिट अथवा व्यापिटों के निजी प्रयोग के लिए सेवाएं; अथवा

(ठ) अवायवियिक सेवाएं प्राप्त करने वाले किसी व्यापिट अथवा व्यापिटों की किसी फर्म (कंपनी के ग्रालावा) को अवायवियों अथवा क्रेडिट देने वाले व्यापिट का कोई कर्मचारी जैसा कि अनुच्छेद 14 में परिभासित है।

(४) पैरा १ और २ के उपदेश उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, पदि रायलिंटों का हितमाली स्थानी व्यक्ति जो किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिनमें रायलिंटों उद्भव होनी है, वहाँ पर स्थित किसी स्थानी संस्थान के माध्यम से अपार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस मम्पति के अधिकार अथवा सेवाओं के संबंध में रायलिंटों प्रदा की जाती है अथवा क्रेडिट की जाती है वे प्रभावी रूप से ऐसे स्थानी संस्थान अथवा निश्चित स्थान से संबंधित हैं। ऐसे मामले में अनुच्छेद २ अथवा अनुच्छेद १४ के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होगे।

(५) एक संविदाकारी राज्य में रायलिंटों तक उद्भव हुई मानी जाएंगी, जब रायलिंटों प्रदा करने वाला स्वयं राज्य अथवा उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई व्यक्ति जो कर के प्रयोजनों के लिए उस राज्य का निवासी हो। लेखापि, जहाँ रायलिंटों प्रदा करने वाले व्यक्ति को, वहाँ वह किसी मंविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो एक संविदाकारी राज्य में अथवा दोनों संविदाकारी ग्रन्थों के बाहर उसका कोई स्थानी संस्थान अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायलिंटों प्रदा करने के वचन दिया गया हो और ऐसी रायलिंटों उस स्थानी संस्थान अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन की जाती हों, वहाँ पर ऐसी रायलिंटों उस संविदाकारी राज्य में 'उद्भव हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थानी संस्थान अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

(६) जहाँ रायलिंटों का प्रदाकर्ता और हितमाली स्थानी व्यक्ति के बीच अथवा उस दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण प्रदा की गई अथवा क्रेडिट की गई अन्यलिंटों की रकम, जिसके लिए इसकी प्रदाकर्ता की गई थी, अथवा नेडिट की गई थी उस रकम से बहु जानी है जिसकी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में प्रदाकर्ता तथा हितमाली स्थानी व्यक्ति के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध के बल अंतिम विनियोग रकम पर ही लागू होगे। उस मामले में, अथवा की गई अथवा क्रेडिट की गई रायलिंटों के प्रतिविवत आग पर, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के करों में संबंधित कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा रहेगा अस्ति कि इस कानून के अन्य लालंधों का पालन किया जाता है।

अनुच्छेद—१३

सम्पत्ति का अन्तरण

१. किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद ६ में उल्लिखित, उस अनुच्छेद में की गई अवस्था के अनुसार, दूसरे संविदाकारी राज्य में नियन्त्रणात्मक सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाली आय अथवा अधिकारों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

२. अनुच्छेद ६ में उल्लिखित आन्तरिक सम्पत्ति से भिन्न किसी ऐसी संपत्ति के अन्तरण में प्राप्त हुई आय अथवा अधिकारों पर, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी स्थानी संस्थान की अपार अधिकारिक संपत्ति के आग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक प्रथम अधिकार राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निवासन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संबंधित हो, जिसमें ऐसी किसी स्थानी संस्थान (अक्षेत्र अथवा अनुपर्याप्त उच्चम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण में प्राप्त होने वाली आय अथवा अधिकारों ही आमिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

३. अन्तरराष्ट्रीय यात्रायात में ज्ञानां जाने वाले अस्थानों अथवा वायुयातों के अंतरण से अथवा जैसे कि अनुच्छेद ६ में निर्दिष्ट है, से भिन्न

किसी संपर्क के अन्तरण से प्राप्त आय अथवा अधिकारी पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा जिसमें कि वह उद्यम, जिसने जलवायनों और वायुवायनों का संचालन किया था, स्थित है।

4. किसी एक संविदाकारी राज्य में उस कामनी के शेयरों अथवा नुन्य हिस्तों के अन्तरण से प्राप्त आय अथवा अधिकारी पर किसी परिस्थितियों में अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट वास्तविक सम्पत्ति पूर्ण रूप से अथवा मुक्त रूप से शामिल है और जैसे कि उस अनुच्छेद में उल्लिखित है, पर उस राज्य में कर लगेगा।

5. किसी कंपनी के शेयरों अथवा तुल्य हिस्तों के अन्तरण से प्राप्त आय अधिकारी पर जो पैराग्राफ (4) में निर्दिष्ट से भिन्न हों, उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जहाँ वह कंपनी स्थित है।

6. इस कारार में वर्णित किसी बात के होने हुए भी, उस संपर्क को छोड़कर जिस पर पैराग्राफ (1), (2), (3), (4) और (5) लागू होते हैं किसी अन्य संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त पूर्णांगत स्वरूप के अनुसारी के कराधार से संबंधित किसी संविदाकारी राज्य के किसी कानून की लागू करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

किसी अधिक अथवा अधिकारी की कर्म (कामनी के अलावा,) जो कि किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित है उसके द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकालायों से प्राप्त आय पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा यदि :

(क) अधिक अथवा कर्म को प्राप्ते अथवा कर्म के कार्यकालायों के निष्पादन के प्रयोगनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध न हो, उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी ही आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निष्कृत स्थान पर किए गए कार्यकालायों के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि किसी अधिक द्वारा अथवा किसी कर्म के मामले में, कर्म के एक या अधिक सदस्यों द्वारा (अकेने अथवा मिलकर) दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की अवधि अथवा अवधियां आय वाले वर्ष में कुम मिलकर 183 दिन प्रथमा इसमें प्रधिक न हो सो उस मामले में, उतनी ही आय पर जो व्यावसायिक उस अधिक, उस सदस्य अथवा उत्तम सदस्यों के कार्यकालायों से उस दूसरे राज्य में प्राप्त हुई हो, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद के अर्थ विस्तार के अन्तर्गत वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, वैधिक अथवा अध्ययन संबंधी स्वतंत्र कार्यकालायों का निष्पादन स्थान विकिस्तकों, शाल विकिस्तकों, वकीलों, हृजीनियरों, वायुविदों, उत्तम विकिस्तकों स्थान लेखांतरों, द्वारा निगादि ; स्वतंत्र स्वरूप के कार्यकालाय प्राप्ति है।

अनुच्छेद 15

पराप्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 और 20 के उल्लंघन के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासी

है किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त सेवन, माझूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि इन प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहाँ से प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ (1) के उल्लंघनों के होने हुए भी, किसी अधिक द्वारा जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिलिप्ति राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता आय वाले वर्ष के द्वितीय कुल मिलकर 183 दिन से अवधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में भीजूद रहा हो ;

(ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से द्वारा किया जाता है, जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थावी संस्थापन अथवा किसी नियित स्थान के कार्यधार सामांग का निर्धारण करते समय काटा नहीं जाता हो, जो नियोजक के दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्व के उल्लंघनों के होने हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में किसी जलवायन अथवा वायुवायन पर सदाचार होकर उसके परिवाहन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 16

निदेशकों की फीस

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कामनी के निदेशक मण्डल के एक सदस्य के रूप में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, प्राप्त निदेशक की फीस और अन्य समलय अवधियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 17

मनोरंजनकर्ता

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उल्लंघनों के होने हुए भी, किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासीयों द्वारा मनोरंजनकर्ताओं के रूप में जैसे यिन्टर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकारों, संगीतकारों और द्विलाइयों के रूप में, दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार समझ किए गए अवधने व्यक्तिगत कार्यकालायों से प्राप्त आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता द्वारा किए गए अविवाहन कार्यकालायों से उद्भूत आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता को प्रेषभूत नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, तो अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उल्लंघनों के होने हुए भी उस आधारपर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता ने कार्यकालाय समझ किए हैं।

3. वैराग्याक (1) के उपवन्दों के होते हुए भी किसी मनोरंजन कर्ता द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैमियत से किए गए मनोरंजनकर्ता के व्यक्तिगत कार्यकलापों में अधित आय प्रथमोलिंगित संविदाकारी राज्य में ही करारेय होनी यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के कार्यकलाप पूर्ण रूप से अथवा अंशिक रूप से प्रथमोलिंगित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निवास तथा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समर्पित हों।

4. वैराग्याक (2) स्थानुच्छेद 7, 14 तथा 15 के उपवन्दों के होते हुए भी, जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता द्वारा मनोरंजनकर्ता की हैमियत से किसी गांविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता को प्राप्त नहीं होती है अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस सामने में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही करारेय होनी यदि वह दूसरा अवक्ष उम दूसरे राज्य की सार्वजनिक निवास तथा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्पित हो।

अनुच्छेद 14

पैण्ड और वायिकी

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी को प्रथम पैण्ड (अनुच्छेद 19 में विविध वैण्डों को छोड़कर) और वायिकियों पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।

2. "वायिकी" शब्द का अर्थ उभ उल्लिखित राशि से है जो उन अथवा घन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिकल के लिए अद्यायिता करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवन पर्याप्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निर्दिष्ट समयावधि के द्वारा उल्लिखित समय पर सामयिक रूप से देय हो।

अनुच्छेद 19

मरकारी सेवा

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा उम राज्य के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को, सरकारी कार्यकलापों के नियंत्रण के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में उसी की गई पैण्डत अथवा वायिकी से विशेष पारिश्रमिक की नागि केवल उसी राज्य में करारेय होगी। तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर सकेगा यदि सेवाएँ उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और प्राप्तकर्ता उस दूसरे राज्य का निवासी हो जो :

(क) उस राज्य का रान्द्रि करो; अथवा

(ख) मात्र सेवाएँ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य अथवा उसके एक राजनीतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई

सेवाओं के संबंध में उस राज्य अथवा उपप्रभाग अथवा प्राप्तिगण द्वारा किसी व्यक्ति को उसी की गयी अथवा उसके द्वारा सुनित की गयी विविधों में से उसी की गयी पेशन पर उसी राज्य में कर लग सकेगा तथापि, ऐसी पेशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में लेवल तभी कर लग सकेगा यदि वह प्राप्तकर्ता उस दूसरे राज्य का निवासी और नागरिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपर्युक्त परिस्थितियों के अनुसार यथोविन रूप से, एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनीतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसी कारबाह के संबंध में प्रदान की गयी सेवाओं के सिलसिले में प्राप्त पारिश्रमिक और पेशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 20

प्राधानिक और अध्यापक

1. यदि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई निवासी प्राधानिक अथवा अध्यापक दो वर्ष से अनधिक प्रथमित के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य की धाका पर किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल अथवा अन्य शैक्षिक संस्थान में अध्यापन अथवा उच्च अध्ययन अथवा प्रतुसंधान कार्य के प्रयोजनार्थ जाता है और यदि वह व्यक्ति ऐसे अध्यापन, उच्च अध्ययन अथवा अनुसंधान के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो उस पर उस दूसरे राज्य में कर के उस सीमा तक छूट मिलेगी जिस सीमा तक ऐसे पारिश्रमिक पर, अथवा इस अनुच्छेद की लागू करने पर, प्रथमोलिंगित राज्य में कर सकेगा।

2. यह अनुच्छेद विषयी प्राधानिक अथवा अध्यापक को जोध कार्य से प्राप्त पारिश्रमिक पर उस स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि अनुसंधान मूल्यानुपाती विविध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

अनुच्छेद 21

छात्र और प्रशिक्षु

यदि कोई छात्र अथवा प्रशिक्षु जो संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य का दीरा करने से तुरन्त पहले उस राज्य का निवासी था, और जो मात्र अपनी अथवा प्रशिक्षु नी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजना उस दूसरे राज्य में अस्थाई रूप से उपस्थित है तथा उस प्रयोजने अथवा प्रशिक्षु के भरण पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य से आहूर के स्रोतों से अद्यायिता प्राप्त होती है, तो उन अद्यायितों पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट मिलेगी।

अनुच्छेद 22

आय जिसका स्पष्टता उल्लेख नहीं है

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी की आय की उन मदों पर, जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेद में स्पष्टता उल्लेख नहीं है, केवल उस राज्य में ही कर सकेगा।

2. तथापि, संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में लोतों से व्युत्पन्न किसी ऐसी आय पर उम दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

3. पैरा (1) के उपबंध, संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी द्वारा व्युत्पन्न आय पर उग स्थिति में लागू नहीं होगे यदि वह आय दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थाई सम्पादन प्रथवा निश्चित स्थान से प्रथवा रूप से संबंधित हो। ऐसे किसी मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 प्रथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होगे।

अनुच्छेद 23

आय का लोन

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी द्वारा व्युत्पन्न आय, लाभ प्रथवा अनुलाभ, जिन पर अनुच्छेद 6 से 8, अनुच्छेद 10 से 20 और अनुच्छेद 22 में से किसी एक प्रथवा एक से अधिक के तहत दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, उन्हें उम दूसरे राज्य के कर से संबंधित कानून के प्रयोजनार्थ उम दूसरे राज्य में लोतों में प्राप्त आय की रूप में समझा जाएगा।

2. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी द्वारा व्युत्पन्न आय, लाभ प्रथवा अनुलाभ, जिन पर अनुच्छेद 6 से 8, अनुच्छेद 10 से 20 और अनुच्छेद 22 में से एक प्रथवा एक से अधिक के तहत दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, उन्हें अनुच्छेद 24 तथा प्रथमो-स्थिति राज्य के कर से संबंधित कानून के प्रयोजनार्थ उम दूसरे राज्य में लोतों से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा।

अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान के अपाकरण के तरीके

1. (क) आस्ट्रेलिया से याहर के किसी देश में प्रवस्त आस्ट्रेलियाई कर के प्रति ईडिट की अनुमति से संबंधित समय-समय पर प्रवृत्त आस्ट्रेलियाई कानून के उपबंधों के प्रध्यधीन (जो इसके सामान्य मिदालों को प्रभावित नहीं करेंगे) आस्ट्रेलिया के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में लोतों से व्युत्पन्न आय के संबंध में, भारतीय कानून के अंतर्गत और इस करार के अनुसार प्रदल भारतीय कर, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से प्रथवा कटौती द्वारा प्रदा किया गया हो, जो उस आय के संबंध में संदेश आस्ट्रेलियाई कर के प्रति ईडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी।

(ख) जहां कोई कम्पनी, जो भारत की निवासी कंपनी है और आस्ट्रेलियाई कर के प्रयोजनों के लिए आस्ट्रेलिया की निवासी नहीं है, यदि यह किसी ऐसी कम्पनी को लाभांश देती है जो आस्ट्रेलिया की निवासी कंपनी है और जो प्रथमोलिंगित कंपनी के सामान्यकार प्रक्रिया के कम से कम 10 प्रतिशत भाग पर प्रत्यक्ष प्रथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रखती है, तो उम स्थिति में उप पैरा (1) में निर्दिष्ट ईडिट में उम प्रथमोलिंगित कंपनी के लाभ के उस भाग के संबंध में उसके द्वारा प्रदल भारतीय कर शामिल होगा जिसमें से लाभांश दिया गया हो।

2. पैरा (1) में, यदा किए गए भारतीय कर में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) उप पैरा (ख) के अध्यधीन, भारतीय कर में संबंधित भारतीय कानून के तहत और इस प्रकार के अनुमार, भाफ की गई भारतीय कर की किसी रकम के बराबर की राशि, आय पर भारतीय कर के रूप में संदेश हो गयी होती यदि निम्नलिखित के अनुमार उम आय पर भारतीय कर से कोई छूट प्रथवा उममें कोई कटौती नहीं की गई होती;

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (4), 10 (15)

(iv), 10क, 10ख, 80जारी, 80जारी प्रथवा 80म, जही तक उनके उपबंध इस करार पर इन्वाक्शर किए जाने की सारी रकम के प्रवृत्त ये श्रीग जिन्हें नव में संगोष्ठित नहीं किया गया है प्रथवा उममें केवल मामूली से संगोष्ठित किए गए हैं ताकि उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव न पहुँचे; प्रथवा

(ii) अन्य कोई उपबंध, जिसे तदनल्लर भारतीय कर से छूट देने प्रथवा उममें कटौती करने के लिए बनाया जाए, जिसके लिए आस्ट्रेलिया का विन मंत्रालय और भारत का वित मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर पत्रों के आदान-प्रदान के जरिये यह मान हो श्रीग उसका मुख्य स्वरूप वशी बना रहे, यदि उम उपबंध को उमके बाद संगोष्ठित नहीं किया गया है प्रथवा उममें केवल मामूली सा संगोष्ठित किया गया है ताकि उमके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पहुँचे; और

(ज) आस्ट्रेलिया के किसी निवासी के द्वारा व्युत्पन्न व्याज के उम मामले में, जिस पर उप पैरा (क) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन भारतीय कर से छूट प्राप्त है, वह रकम जो भारतीय कर के रूप में संदेश हो जाती यदि व्याज पर इस प्रकार की छूट नहीं दी जाती और यदि अनुच्छेद 11 के पैरा (2) में निर्दिष्ट कर मकल व्याज के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता।

3. पैरा (2) केवल प्रथम 10 वर्षों के किसी वर्ष में व्युत्पन्न आय के संबंध में ही लागू होगा जिसके बारे में इस करार के अनुच्छेद 28 का उप पैरा (1)(क)(ii) लागू होता है अथवा बाद के किसी वर्ष की आय, जिसके संबंध में इस प्रयोजनार्थ पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा संविदाकारी राज्यों में सहमति हई हो।

4. भारत के मामले में, दोहरे कराधान का परिहार निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :

(क) आस्ट्रेलिया के कानूनों के तहत और इस करार के उपबंधों के अनुमार आस्ट्रेलिया में लोतों से प्राप्त आय के संबंध में भारत के किसी निवासी द्वारा प्रदल कर की रकम, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से आय की गई हो अथवा कटौती के रूप में प्रदा की गई हो, जिस पर भारत तथा आस्ट्रेलिया, दोनों देशों में कर लगाया गया हो, उस पर ऐसी आय के संबंध में

संदेश भारतीय कर के प्रति ईडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी किन्तु यह गणि भारतीय कर को उम्म रकम के अनुपात से अधिक नहीं हो जो ऐसी आय के मिलनिये में भारतीय कर के अनुमार प्रभाव समस्त आय पर प्रदल हो ; और

(ब) उपर्युक्त पैग (क) में निदिष्ट कैडिट के प्रयोजनों के लिए यदि कोई कंपनी भारत की निवासी है जिसके द्वारा अनिकर संदेश है, तो भारतीय कर के प्रति विद्या जाने वाला ईडिट, भारत में उम्म कंपनी द्वारा संदेश आयकर के प्रति पहली बार अनुरोध पर विद्या जाएगा और, यदि कुछ सेप रह जाए तो वह भारत में उम्मके द्वारा संदेश अनिकर के प्रति दिया जाएगा ।

5. यदि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई निवासी इस करार के उपबन्धों के अनुमार गेमी आय प्राप्त करता है जिस पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा, तो प्रथमोनिवित राज्य उस निवासी की बाकी आय पर संदेश आपाते कर की रकम को परिकलित करने में उम्म आय को हिसाब में ले सकता है ।

अनुच्छेद 25

पाराम्परिक करार कार्यविधि

1. यदि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अवका दोनों संविदाकारी राज्यों के कराधान प्राधिकारी की कार्रवाईयों के परिणामतः उम्म अवकित पर इस करार के उपबन्धों के अनुमार कर नहीं लगाया जाएगा है अवका नहीं लगाया जाएगा, तो वह अवकित उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपायों के होने हुए भी, उम्म संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है । यह मामला कार्रवाई की प्रथम प्रधिसूचना की तारीख से तीन अपौं के भीतर अवकण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके कारण वह कर लगाया गया है जो इस करार के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को यह दोषा उपचित नहीं और यदि वह किसी समुचित हल पर पहुँचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के निवासा की ईडिट से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के नाम उम्म मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार जो हल निकलेगा उसे बार्यान्वित किया जाएगा जाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्षयों न हो ।

3. इस करार को लागू करने में यदि कोई कठिनाइयों अवका शक्ति उपर्युक्त तीन संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें संयुक्त स्पष्ट से हल करने का प्रयास करेंगे ।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के उपबन्धों को लागू करने के प्रयोगनार्थ पक्कादूसरे के साथ सीधे पद्धत्यवहार कर सकते हैं ।

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो हस करार अवका संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए अवकणक है जिन पर यह करार लागू होता है, जहाँ तक कि उनके अधीन की गई कराधान अवस्था, अवका करों के अवर्वदन अवका परिहार, अवका ऐसे करों से संबंधित जालमाजी को रोकने के लिए की गई अवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद-1 द्वारा प्रतिवर्धित नहीं है । किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और इसे ऐसे अवकितयों अवका प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रणासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जाएगा जो उन करों के निर्धारण अवका उगाही, उनके संबंध में प्रवर्तन अवका अधियोजन अवका उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हों, जिन पर यह करार लागू होता है और उसका इस्तेमाल केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा वे इस सूचना को मार्बंजिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाहियों अवका न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. मध्यम प्रविकरी परामर्श करके उन मामलों में संबंधित अपीलों तरीकों और तकनीकों को विकसित कर सकते हैं जिनके संबंध में ऐसी सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा । सूचना का आदान-प्रदान मामलों विषेष के सन्दर्भ में सामान्य रूप से होगा अवका अनुरोध करने पर, अवका दोनों तरह से । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सूचना की उग सूची पर समय-समय पर सहमत हो जाएगी वे अपीलों को निर्धारण कर सकते हैं जिसे भास्त्व तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. किसी भी स्थिति में, वैश 1 के उपबन्धों का धर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वे एक संविदाकारी राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी को निम्न-निवित के लिए बाध्य करते हैं:—

(क) ऐसे प्रणासनिक उपाय करना जो उम्म अवका दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अवका प्रवका प्रणासनिक प्रथा से भिन्न हों;

(ख) ऐसी सूचना देना जो उम्म अवका दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अवका प्रणासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त करने योग्य नहीं हो;

(ग) ऐसी सूचना देना, जिसमें कोई व्यापारिक व्यावासायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अवका दूति संबंधी गुप्त भेद अवका व्यापारिक प्रक्रिया प्रकट होती हो अवका ऐसी सूचना देना जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो ।

अनुच्छेद—27

राजनियक और कौनुनी प्रतिक्रिया

इस कारार को किसी भी दात में राजनियक अवधार और उन्होंने अधिकारियों के उन वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पहेगा औं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य दिवसों के अन्तर्गत अवधार विशेष अन्तर्राष्ट्रीय करारों के प्रावधारों के अन्तर्गत प्राप्त है।

अनुच्छेद—28

प्रवर्तन

1. यह कारार उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको संविशाकारी राज्य राजनियक माध्यम से एक अनुच्छेद को इस भारे में सूचित करते हुए दिया गया है और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य दिवसों के अन्तर्गत अवधार विशेष अन्तर्राष्ट्रीय करारों के प्रावधारों के अन्तर्गत प्राप्त है।

(क) आस्ट्रेलिया में:

(i) किसी रैरनिवासी द्वारा व्युत्पन्न आय पर प्रबंधारण करने के संबंध में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह कारार प्रवृत्त होता है उसके बाद के परवर्ती कैलेंडर वर्ष में एक जुलाई को अवधार उसके पश्चात् व्युत्पन्न आय के संबंध में; और

(ii) अन्य आस्ट्रेलियाई कर के संबंध में, जिस कैलेंडर वर्ष से यह कारार प्रवृत्त होता है उसके बाद के परवर्ती कैलेंडर वर्ष में एक जुलाई को अवधार उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी आय-वर्ष की आय, लाभों अवधार अनुताभावों के संबंध में;

(ख) भारत में:

जिस कैलेंडर वर्ष से यह कारार प्रवृत्त होता है उसके बाद के परवर्ती वर्ष में एक अप्रैल को अवधार उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी आय-वर्ष में उद्भूत आय, लाभों अवधार अनुताभावों के संबंध में।

2. आस्ट्रेलिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के थीव 31 मई, 1983 को कैनबरा में हस्ताक्षित अन्तरराष्ट्रीय आय परिवहन से व्युत्पन्न आय के दोहरे कराधार के परिवर्त के लिए किए गए कारार (जिसे इस अनुच्छेद में "1983 का कारार" कहा गया है) का प्रभाव उन करों के संबंध में, जिन पर यह कारार लागू होता है उस समय समाप्त हो जाएगा जब इस कारार के उपर्युक्त पैरा (1) के अनुसार प्रभावी बन जाएंगे।

3. 1983 का कारार उस प्रन्तिम तारीख की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा जिसको इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपक्रमों के अनुसार यह प्रभावी होगा।

अनुच्छेद—29

पर्यावरण

यह कारार प्रनिष्ठित समय तक लागू रहेगा, किन्तु दोनों में से कोई भी संविशाकारी राज्य, इस कारार के प्रवृत्त होने की तारीख से 5 वर्ष की

समाप्ति के पश्चात् होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष में 30 जून को अवधार उससे पहले, दूसरे संविशाकारी राज्य और राजनियक माध्यम से पर्यावरण संबंधी निश्चित नोटिस दे सकता है और उस दशा में इस कारार का प्रभाव इस प्रकार समाप्त हो जाएगा :

(क) आस्ट्रेलिया में:

(i) किसी रैरनिवासी द्वारा व्युत्पन्न आय पर प्रबंधारण कर के संबंध में, जिस कैलेंडर वर्ष में पर्यावरण का नोटिस दिया गया हो, उसके बाले परवर्ती वर्ष में एक जुलाई को अवधार उसके बाद व्युत्पन्न आय के संबंध में; और

(ii) अन्य आस्ट्रेलिया कर के संबंध में, जिस कैलेंडर वर्ष में पर्यावरण का नोटिस दिया गया हो, उसके बाले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में एक जुलाई की अवधार उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी आय-वर्ष की आय, लाभों अवधार अनुताभावों के संबंध में;

(ख) भारत में:

जिस कैलेंडर वर्ष में पर्यावरण का नोटिस दिया गया हो, उसके बाले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में एक अप्रैल की अवधार उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी आय-वर्ष में उद्भूत होने वाली भारत, लाभों अवधार अनुताभावों के संबंध में।

जिसके साथ में, इसमें निम्न विधिग्रन्थ प्राधिक्रिया, प्रांतीकान्तरियों ने इस कारार पर दृस्तावत किए हैं।

कैनबरा में वर्ष एक हजार ती सौ हजार से के जुलाई माह के पश्चीमे दिन को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दोनों पोर्टिंग में प्रदान किया गया, जिसके दोनों पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे। इन दो पाठों के बीच विप्रवासी की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

आस्ट्रेलिया सरकार
की ओर से

[प्रधिसूचना में, 8984 (फा. सं. 501/1/79-एफ. टी. जी.)]

एन. मी. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

FOREIGN TAX DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1992

(INCOME TAX)

G.S.R. 60(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Australia for the avoidance of

double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 30th day of December, 1991, on the exchange of notes notifying each other that the last of such things has been done as is necessary to give the said Agreement the force of law in India and in Australia, in accordance with paragraph (1) of Article 28 of the said Agreement :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

**ANNEXURE
AGREEMENT
BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDIA**

AND

THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA

FOR

**THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND**

**THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of Australia,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

(1) The existing taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) in Australia :

the income tax, and the resource rent tax in respect of offshore projects relating to exploration for or exploitation of petroleum

resources, imposed under the federal law of the Commonwealth of Australia;

(b) in India :

- (i) the income tax including any surcharge thereon; and
- (ii) the surtax imposed on chargeable profits of companies.

(2) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed under the federal law of the Commonwealth of Australia or the law of the Republic of India after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in the laws of their respective States relating to the taxes to which this Agreement applies.

ARTICLE 3

General Definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "Australia", when used in a geographical sense, excludes all external territories other than :
 - (i) the Territory of Norfolk Island;
 - (ii) the Territory of Christmas Island;
 - (iii) the Territory of Cocos (Keeling) Islands;
 - (iv) the Territory of Ashmore and Cartier Islands;
 - (v) the Territory of Heard Island and McDonald Islands; and
 - (vi) the Coral Sea Islands Territory,

and includes any area adjacent to the territorial limits of Australia (including the Territories specified in sub-paragraphs (i) to (vi) inclusive, in respect of which there is for the time being in force, consistently with international law, a law of Australia dealing with the exploitation of any of the natural resources of the seabed and sub-soil of the continental shelf);

- (b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and the air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions,

according to the Indian law and in accordance with international law;

(c) the terms "Contracting State", "one of the Contracting States" and "other Contracting State" mean, as the context requires, Australia or India, the Governments of which have concluded this Agreement;

(d) the term "person" includes an individual, a company, any other body of persons and any other entity which is treated as a taxable units for tax purposes;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;

(f) the term "enterprise of one of the Contracting States" and "enterprise of the other Contracting State" mean an enterprise carried on by a resident of Australia or an enterprise carried on by a resident of India, as the context requires;

(g) the term "tax" means Australian tax or Indian tax, as the context requires;

(h) the term :

- (i) "Australian tax" means tax imposed by Australia; and
- (ii) "Indian tax" means tax imposed by India, being tax to which this Agreement applies by virtue of Article 2, but neither term includes any amount which represents a penalty or fine or interest imposed under the law of either Contracting State relating to its tax;

(i) the term "competent authority" means, in the case of Australia, the Commissioner of Taxation or an authorised representative of the Commissioner and, in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and

(j) the term "year of income", in relation to Indian tax, means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961.

(2) In the application of this Agreement by a Contracting State, any term not defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State from time to time in force relating to the taxes to which this Agreement applies.

ARTICLE 4

Residence

(1) For the purposes of this Agreement, a person is a resident of one of the Contracting States if the person is a resident of that Contracting State for the purposes of its tax. However, a person is not a resident of a Contracting State for the purposes of this Agreement if the person is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

(2) Where, by reason of the provisions of paragraph (1), an individual is a resident of both Contracting States, then the status of that person shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) the person shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State in which a permanent home is available to the person;
- (b) if a permanent home is available to the person in both Contracting States, or in neither of them, the person shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State with which the person's personal and economic relations are closer (centre of vital interests).

For the purposes of this paragraph, an individual's citizenship of a Contracting State as well as that person's habitual abode shall be factors in determining the degree of the person's personal and economic relations with that Contracting State.

(3) Where, by reason of the provisions of paragraph (1), a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

(1) For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources ;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agricultural, pastoral, forestry or plantation activities are carried on;
- (i) premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (j) an installation or structure, or plant or equipment, used for the exploration for or exploitation of natural resources;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project, or supervisory activities in connection with such a site or project, where that site or project exists or those activities are carried on

(whether separately or together with other sites, projects or activities) for more than 6 months.

(3) An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in one of the Contracting States and to carry on business through that permanent establishment if :

- (a) substantial equipment is being used in that State by, for or under contract with the enterprise;
- (b) it carries on activities in that State in connection with the exploration for or exploitation of natural resources in that State; or
- (c) it furnishes services, including managerial services and those mentioned in subparagraphs (3) (h) to (k) of Article 12 but not those services in respect of which payments or credits that are royalties as defined in Article 12 are made, within one of the Contracting States through employees of other personnel, but only if those services are furnished within that State :
 - (i) for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12 month period; or
 - (ii) for another enterprise if both enterprises are within either of the relationships described in subparagraphs (1)(a) and (b) of Article 9.

(4) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment merely by reason of :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise; or
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

However, the preceding provisions of this paragraph shall not apply where an enterprise of one of the Contracting States maintains in the other Contracting State a fixed place of business for any purpose other than those specified in this paragraph.

(5) A person acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first mentioned State if :

- (a) the person has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless the person's activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) the person has no such authority, but habitually maintains in that State a stock of goods or merchandise from which the person regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise;
- (c) the person habitually secures orders in that State, wholly or principally for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, or controlled by or subject to the same common control as, that enterprise; or
- (d) in so acting, the person manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.

(6) An enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where that person is acting in the ordinary course of the person's business as such a broker or agent. However, when the activities of such a broker or agent are carried on wholly or principally on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, or controlled by or subject to the same common control as, that enterprises, the person will not be considered a broker or agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

(7) That fact that a company which is a resident of one of the Contracting States controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself make either company a permanent establishment of the other.

(8) The principles set forth in the preceding paragraphs of this Article shall be applied in determining for the purposes of paragraph (5) of Article 11 and paragraph (5) of Article 12 of this Agreement whether there is a permanent establishment outside both Contracting States, and whether an enterprise, not being an enterprise of one of the Contracting States, has a permanent establishment in one of the Contracting States.

ARTICLE 6

Income from Real Property (Immovable Property)

(1) Income from real property may be taxed in the Contracting State in which that property is situated.

(2) For the purposes of this Article, the term "real property":

(a) in the case of Australia, has the meaning which it has under the laws of Australia and shall include:

(i) a lease of land and any other interest in or over land, whether improved or not; and

(ii) a right to receive variable or fixed payments either as consideration for the working of or the right to work or explore for, or in respect of the exploitation of, mineral or other deposits, oil or gas wells, quarries or other places of extraction or exploitation of natural resources; and

(b) in the case of India, means such property which, according to the laws of India, is immovable property and shall include :

(i) property accessory to immovable property;

(ii) rights to which the provisions of the general law respecting landed property apply; and

(iii) usufruct of immovable property and rights to receive variable or fixed payments either as consideration for the working of or the right to work or explore for, or in respect of exploitation of, mineral or other deposits, oil or gas wells, quarries or other places of extraction or exploitation of natural resources.

(3) A lease of land, any other interest in or over land and any rights or property referred to in any of the sub-paragraphs of paragraph (2) shall be regarded as situated where the land, mineral or other deposits, oil or gas wells, quarries, natural resources or property, as the case may be, are situated or where the exploration may take place.

(4) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of real property.

(5) The provisions of paragraphs (1), (3) and (4) shall also apply to the income from real property of an enterprise and to income from real property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

(1) The profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:

(a) that permanent establishment; or

(b) sales within that other Contracting State of goods or merchandise of the same or a similar kind as those sold, or other business activities of the same or a similar kind as those carried on, through that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment or with other enterprises with which it deals.

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions, in accordance with and subject to the limitations of the law relating to tax in the Contracting State in which the permanent establishment is situated, expenses of the enterprise, being expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment (including executive and general administrative expenses so incurred), whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(5) Where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination by the taxation authority of one of the Contracting States or the ascertaining thereof by that authority presents exceptional difficulties, nothing in this Article shall affect the application of any law of that State relating to the determination of the tax liability of a person, provided that the law shall be applied, so far as the information available to that authority permits, in accordance with the principles of this Article.

(6) For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

(8) Nothing in this Article shall affect the operation of any law of a Contracting State relating to tax imposed on profits from insurance with non-residents provided that if the relevant law in force in either Contracting State at the date of signature of this Agreement is varied (otherwise than in minor respects so as not to affect its general character) the Contracting States shall consult with each other with a view to agreeing to any amendment of this paragraph that may be appropriate.

(9) Where :

- (a) a resident of one of the Contracting States is beneficially entitled, whether directly or through one or more interposed trust estates, to a share of the business profits of an enterprise carried on in the other Contracting State by the trustee of a trust estate other than a trust estate which is treated in that other State as a company for tax purposes; and
- (b) in relation to that enterprise, that trustee would, in accordance with the principles of Article 5, have a permanent establishment in that other Contracting State,

the enterprise carried on by the trustee shall be deemed to be a business carried on in that other Contracting State by that resident through a permanent establishment situated therein and that share of business profits shall be attributed to that permanent establishment.

ARTICLE 8

Ships and Aircraft

(1) Profits from the operation of ships or aircraft, including interest on funds connected with that operation, derived by a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), such profits may be taxed in the other Contracting State where they are profits from the operations of ships or aircraft confined solely to places in that other State.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall apply in relation to the share of the profits from the operation of ships or aircraft derived by a resident of one of the Contracting States through participation in a pool service, in a joint transport operating organisation or in an international operating agency.

(4) For the purposes of this Article, profits derived from the carriage by ships or aircraft of passengers, livestock, mail, goods or merchandise shipped in a Contracting State for discharge at another place in that State shall be treated as profits from operations of ships or aircraft confined solely to places in that State.

ARTICLE 9

Associated Enterprises

(1) Where :

- (a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions operate between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which might be expected to operate between independent enterprises dealing wholly independently with one another, then any profits which, but for those conditions, might have been expected to accrue to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person, including determinations in cases where the information available to the taxation authority of that State is inadequate to determine the income to be attributed to an enterprise, provided that that law shall be applied, so far as is practicable to do so, consistently with the principles of this Article.

(3) Where profits on which an enterprise of one of the Contracting States have been charged to tax in that State are also included, by virtue of paragraph (1) or (2), in the profits of an enterprise of the other Contracting State and charged to tax in that other State, and the profits so included are profits which might have been expected to have accrued to that enterprise of the other State if the conditions operative between the enterprises had been those which might have been expected to have operated between independent enterprises dealing wholly independently with one another, then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged on those profits in the first-mentioned State. In determining such an adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and for this purpose the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States for the purposes of its tax, being dividends to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

(2) Such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident for the purposes of its tax, and according to the law of that State, but the tax so

charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

(3) The term "dividends" in this Article means income from shares and other income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident for the purposes of its tax.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the dividends, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In any such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States, being dividends to which a person who is not a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, shall be exempt from tax in that other State except insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or fixed base situated in that other State. Provided that this paragraph shall not apply in relation to dividends paid by any company which is a resident of Australia for the purposes of Australian tax and which is also a resident of India for the purposes of Indian tax.

ARTICAL 11

Interest

(1) Interest arising in one of the Contracting States, being interest to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

(2) Such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

(3) The term "interest" in this Article includes interest from Government securities or from bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and interest from any other form of indebtedness as well as all other income assimilated to income from money lent by the law, relating to tax, of the Contracting State in which the income arises, but does not includ interest referred to in paragraph (1) of Article 8.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the interest, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the indebtedness in respect of which

the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political sub-division or local authority of that State or a person who is a resident of that State for the purposes of its tax. Where, however, the person paying the interest, whether the person is a resident of one of the Contracting States or not, has in one of the Contracting States or outside both Contracting States a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where, owing to a special relationship between the payer and the person beneficially entitled to the interest, or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the indebtedness for which it is paid, exceeds the amount which might have been expected to have been agreed upon by the payer and the person so entitled in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the amount of the interest paid shall remain taxable according to the law, relating to tax, of each Contracting State, but subject to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

Royalties

(1) Royalties arising in one of the Contracting States, being royalties to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

(2) Such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed :

(a) in the case of :

(i) royalties referred to in sub-paragraph (3) (b);

(ii) payments or credits for services referred to in sub-paragraph (3)(d), subject to sub-paragraphs (3) (h) to (l), that are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of equipment for which payments or credits are made under sub-paragraph (3) (b); or

(iii) royalties referred to in sub-paragraph (3) (f) that relate to equipment mentioned in sub-paragraph (3) (b);

10 per cent of the gross amount of the royalties; and

(b) in the case of other royalties :

(i) during the first 5 years of income for which this Agreement has effect :

(A) where the payer is the Government or a political sub-division of that State or a public sector company : 15 per cent of the gross amount of the royalties; and

(B) in all other cases : 20 per cent of the gross amount of the royalties; and

(ii) during all subsequent years of income : 15 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" in this Article means payments or credits, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for :

(a) the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark, or other like property or right;

(b) the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;

(c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information;

(d) the rendering of any technical or consultancy services (including those of technical or other personnel) which are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of any such property or right as is mentioned in sub-paragraph (a), any such equipment as is mentioned in sub-paragraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in sub-paragraph (c);

(e) the use of, or the right to use:

(i) motion picture films;

(ii) films or video tapes for use in connection with television; or

(iii) tapes for use in connection with radio broadcasting;

(f) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to in sub-paragraphs (a) to (e); or

(g) the rendering of any services (including those of technical or other personnel) which make available technical knowledge, experience, skill, know-how or processes or consist of the development and transfer of a technical plan or design;

but that term does not include payments or credits relating to services mentioned in sub-paragraphs (d) and (g) that are made:

(h) for services that are ancillary and subsidiary and inextricably and essentially linked, to a sale of property;

(i) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;

(j) for teaching in or by an educational institution;

(k) for services for the personal use of the individual or individuals making the payments or credits; or

(l) to an employee of the person making the payments or credits or to any individual or firm of individuals (other than a company) for professional services as defined in Article 14.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the royalties, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting States, in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the property, right or services in respect of which the royalties are paid or credited are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political subdivision or local authority of that State or a person who is a resident of that State for the purposes of its tax. Where, however, the person paying the royalties, whether the person is a resident of one of the Contracting States or not, has in one of the Contracting States or outside both Contracting States a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred and the royalties are borne by the permanent establishment or fixed base, then the royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where, owing to a special relationship between the payer and the person beneficially entitled to the royalties, or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid or credited, having regard to what they are paid or credited for, exceeds the amount which might have been expected to have been agreed upon by the payer and the person so entitled in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the amount of the royalties paid or credited shall remain taxable according to the law, relating to tax, of each Contracting State, but subject to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

Alienation of Property

(1) Income or gains derived by a resident of one of the Contracting States from the alienation of real property referred to in Article 6 and, as provided in

that Article, situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Income or gains derived from the alienation of property. Other than real property referred to in Article 6, that forms part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State or pertains to a fixed base available to a resident of the firstmentioned State in that other State for the purpose of performing independent personal services, including income or gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

(3) Income or gains derived from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or of property other than real property referred to in Article 6 pertaining to the operation of those ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise which operated those ships or aircraft is a resident.

(4) Income or gains derived from the alienation of shares or comparable interests in a company, the assets of which consist wholly or principally or real property referred to in Article 6 and, as provided in that Article, situated in one of the Contracting States, may be taxed in that State.

(5) Income or gains derived from the alienation of shares or comparable interests in a company, other than those referred to in paragraph (4), may be taxed in the Contracting State of which the company is a resident.

(6) Nothing in this Agreement affects the application of a law of a Contracting State relating to the taxation of gains of a capital nature derived from the alienation of property other than that to which any of paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) apply.

ARTICLE 14

Independent Personal Services

(1) Income derived by an individual or a firm of individuals (other than a company) who is a resident of one of the Contracting States in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless :

- (a) the individual or firm has a fixed base regularly available to the individual or firm in the other Contracting State for the purpose of performing the individual's or the firm's activities, in which case the income may be taxed in that other State but only so much of it as is attributable to activities exercised from that fixed base ; or
- (b) the stay by the individual or, in the case of a firm, by one or more members of the firm (alone or together) in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding 183 days in a year of income, in which case only so much of the income as is derived from the activities of the individual, that member or

those members, as the case may be, in that other State may be taxed in that other State.

(2) The term "professional services" includes services performed in the exercise of independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as in the exercise of the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

Dependent Personal Services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived from that exercise may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph(1), remuneration derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the firstmentioned State if :

- (a) the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in a year of income of that other State ;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other State ; and
- (c) the remuneration is not deductible in determining taxable profits of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by a resident of one of the Contracting States may be taxed in that State.

ARTICLE 16

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of one of the Contracting States as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17

Entertainers

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by residents of one of the Contracting States as entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, musicians and athletes, from their personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of the personal activities of an entertainer as such accrues not to that entertainer but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer are exercised.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), income derived by an entertainer who is a resident of one of the Contracting States, from the entertainer's personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first mentioned Contracting State if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) and Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer in the entertainer's capacity as such in one of the Contracting States accrues not to the entertainer but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

ARTICLE 18

Pensions and Annuities

(1) Pensions (not including pensions referred to in Article 19) and annuities paid to a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.

(2) The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 19

Government Service

(1) Remuneration, other than a pension or annuity, paid by one of the Contracting States or a political sub-division or local authority of that State to any individual in respect of services rendered in the discharge of governmental functions shall be taxable only in that State. However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the recipient is a resident of that other State who :

- (a) is a citizen of that State ; or
- (b) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

(2) Any pension paid by, or out of funds created by, one of the Contracting States or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State

or sub-division or authority shall be taxable only in that State. However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a resident and a citizen of that other State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply, as appropriate in the circumstances, to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by one of the Contracting States or a political sub-division or local authority thereof.

ARTICLE 20

Professors and Teachers

(1) Where a professor or teacher who is a resident of one of the Contracting States visits the other Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or carrying out advanced study or research at a university, college, school or other educational institution, any remuneration that person receives for such teaching, advanced study or research shall be exempt from tax in that other State to the extent to which such remuneration is, or upon the application of this Article will be, subject to tax in the first mentioned State.

(2) This Article shall not apply to remuneration which a professor or teacher receives for conducting research if the research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 21

Students and Trainees

Where a student or trainee, who is a resident of one of the Contracting States or who was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State solely for the purpose of the student's or trainee's education or training, receives payments from sources outside that other State for the purpose of the student's or trainee's maintenance, education or training, those payments shall be exempt from tax in that other State.

ARTICLE 22

Income Not Expressly Mentioned

(1) Items of income of a resident of one of the Contracting States which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

(2) However, any such income derived by a resident of one of the Contracting States from sources in other Contracting State may also be taxed in that other State.

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income derived by a resident of one of the Contracting States where that income is effectively connected with a permanent establishment or fixed base situated in the other Contracting State. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

ARTICLE 23

Source of Income

(1) Income, profits or gains derived by a resident of one of the Contracting States which, under any one or more of Articles 6 to 8, Articles 10 to 20 and Article 22 may be taxed in the other Contracting State, shall for the purposes of the law of that other State relating to its tax be deemed to be income from sources in that other State.

(2) Income, profits or gains derived by a resident of one of the Contracting States which, under any one or more of Articles 6 to 8, Articles 10 to 20 and Article 22 may be taxed in the other Contracting State, shall for the purpose of Article 24 and of the law of the first mentioned State relating to its tax be deemed to be income from sources in that other State.

ARTICLE 24

Methods of Elimination of Double Taxation

(1)(a) Subject to the provisions of the law of Australia from time to time in force which relate to the allowance of a credit against Australian tax of tax paid in a country outside Australia (which shall not affect the general principle hereof), Indian tax paid under the law of India and in accordance with this Agreement, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a person who is a resident of Australia from sources in India shall be allowed as a credit against Australian tax payable in respect of that income.

(b) Where a company which is a resident of India and is not a resident of Australia for the purposes of Australian tax pays a dividend to a company which is a resident of Australia and which controls directly or indirectly not less than 10 per cent of the voting power of the firstmentioned company, the credit referred to in subparagraph (a) shall include the Indian tax paid by that firstmentioned company in respect of that portion of its profits out of which the dividend is paid.

(2) In paragraph (1), Indian tax paid shall include :

(a) subject to sub-paragraph (b), an amount equivalent to the amount of any Indian tax forgone which, under the law of India relating to Indian tax and in accordance with this Agreement, would have been payable as Indian tax on income but for an exemption from, or reduction of, Indian tax on that income in accordance with :

(i) section 10(4), 10(15)(iv), 10A, 10B, 80HHC, 80HHD or 80I of the Income tax Act, 1961, insofar as those provisions were in force on, and have not been modified since, the date of signature of this Agreement, or have been modified

only in minor respects so as not to affect their general character ; or

(ii) any other provision which may subsequently be made granting an exemption from or reduction of Indian tax which the Treasurer of Australia and the Minister of Finance of India agree from time to time in letters exchanged for this purpose to be of a substantially similar character if that provision has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character ; and

(b) in the case of interest derived by a resident of Australia which is exempted from Indian tax under the provisions referred to in subparagraph (a), the amount which would have been payable as Indian tax if the interest had not been so exempt and if the tax referred to in paragraph (2) of Article 11 did not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Paragraph (2) shall apply only in relation to income derived in any of the first 10 years of income in relation to which this Agreement has effect under sub-paragraph (1)(a)(ii) of Article 28 or in any later year of income that may be agreed by the Contracting States in letters exchanged for this purpose.

(4) In the case of India, double taxation shall be avoided as follows :

(a) the amount of Australian tax paid under the laws of Australia and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India in respect of income from sources within Australia which has been subjected to tax both in India and Australia shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax ; and

(b) for the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

(5) Where a resident of one the Contracting States derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement shall be taxable only in the other Contracting State, the firstmentioned State may take that income into account in calculating the amount of its tax payable on the remaining income of that resident.

ARTICLE 25

Mutual Agreement Procedure

(1) Where a person who is a resident of one of the Contracting States considers that the actions of the taxation authority of one or both of the Contracting States result or will result for the person in taxation not in accordance with this Agreement, the person may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present a case to the competent authority of the Contracting State of which the person is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action giving rise to taxation not in accordance with this Agreement.

(2) The competent authority shall endeavour, if the claim appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement. The solution so reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall jointly endeavour to resolve any difficulties or doubts arising as to the application of this Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of giving effect to the provisions of this Agreement.

ARTICLE 26

Exchange of Information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning the taxes to which this Agreement applies insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement, or for the prevention of evasion or avoidance of, or fraud in relation to, such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by the competent authority of a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes to which this Agreement applies and shall be used only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) The competent authorities may, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made. The exchange of information shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases, or both. The competent authorities of the Contracting

States may agree from time to time on the list of the information which shall be furnished on a routine basis.

(3) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on the competent authority of a Contracting State the obligation:

- to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or to supply information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

Diplomatic and Consular Officials

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special international agreements.

ARTICLE 28

Entry into Force

(1) This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting States exchange notes through the diplomatic channel notifying each other that the last of such things has been done as is necessary to give this Agreement the force of law in Australia and in India, as the case may be, and thereupon this Agreement shall have effect:

(a) in Australia:

(i) in respect of withholding tax on income that is derived by a non-resident, in relation to income derived on or after 1 July in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force; and

(ii) in respect of other Australian tax, in relation to income, profits or gains of any year of income beginning on or after 1 July in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;

(b) in India, in respect of income, profits or gains arising in any year of income beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

(2) The Agreement made between the Government of Australia and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation of Income derived from International Air

Transport signed at Canberra on 31 May 1983 (in this Article called "the 1983 Agreement") shall cease to have effect with respect to taxes to which this Agreement applies when the provisions of this Agreement become effective in accordance with paragraph (1).

(3) The 1983 Agreement shall terminate on the expiration of the last date on which it has effect in accordance with the foregoing provisions of this Article.

ARTICLE 29

Termination

This Agreement shall continue in effect indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30 June in any calendar year beginning after the expiration of 5 years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State through the diplomatic channel written notice of cease to be effective.

(a) in Australia :

termination and, in that event, this Agreement shall

(i) in respect of withholding tax on income that is derived by a non-resident, in relation to income derived on or after 1 July in the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and

(ii) in respect of other Australian tax, in relation to income, profits or gains of any year of income beginning on or after 1 July in the calendar year next following that in which the notice of termination is given;

(b) in India, in respect of income, profits or gains arising in any year of income beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Canberra this Twenty fifth day of July One thousand nine hundred and ninety-one in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic, the English text to be the operative one in any case of doubt.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA :

FOR THE GOVERNMENT OF
AUSTRALIA :
[Notification No. 3984 (F. No. 501/1/79-FTD)]
N. C. JAIN, Jt. Secy.